

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा

Dr. Mukesh Pancholi

(II) ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, 1954 –

भारत सरकार द्वारा श्री के. एल. माली की अध्यक्षता में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति 1954 का गठन किया गया, इस समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपे।

समिति के गठन के बाद ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ने अपना विस्तृत अध्ययन सरकार को 1954 में अपना प्रतिवेदन विभिन्न संस्तुतियों के साथ प्रस्तुत किया।

ग्रामीण शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिश –
शिक्षण स्टाँफ –

ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न संस्थानों पर जोर डालते हुए उसमें नियुक्त होने वाले शिक्षण स्टाँफ के संबंध में निम्न सिफारिश की –

- ग्रामीण विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में योग्य शिक्षण स्टाँफ होना चाहिए।
- आधुनिक शिक्षा के निर्माण की अनिवार्यता के आधार पर ग्रामीण संस्थानों में शिक्षण स्टाँफ की भर्ती की जानी चाहिए।

- ग्रामीण उच्च शिक्षा व शिक्षकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय परिषद् का गठन किया जाना चाहिए।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान –

- ग्रामीण उच्च शिक्षा के विकास हेतु लंबे समय से कार्यरत संस्थानों को ग्रामीण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्वास्थ्य, अभियंत्रण, तकनीकी शिक्षा के नवीन महाविद्यालय व विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए।

- ग्रामीण संस्थानों में अलग से अनुसंधान विभाग खोले जाने चाहिए।
- ग्रामीण समस्याओं पर अनुसंधान हो और परिणाम से समस्या का समाधान हो।
- विद्यार्थियों को आवास आदि को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा –

- सार्वजनिक नियुक्तियों के संबंध में ग्रामीण विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली कृषि, स्वास्थ्य, तकनीकी व ग्रामीण सेवा की उपाधियों को वैधता अन्य विश्वविद्यालयों की उपाधियों के समान होनी चाहिए।

- अध्ययन के साथ अंशकालीन रोजगार से जुड़े संयुक्त कार्य को वरीयता होनी चाहिए।
- अध्ययन के साथ स्वतः आय अर्जित करने का अवसर विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए।
- सरकारी व गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ पारस्परिक सहयोग से समस्त कार्य किए जाने चाहिए।
- ग्रामीण सेवा से संबंधित 5 वर्षीय अध्ययन को B.A. के समकक्ष माना जाए व UPSC के द्वारा रोजगार का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

परीक्षा पद्धति -

- विश्वविद्यालय अध्ययन में स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय अध्ययन के उपरांत परीक्षा होनी चाहिए।
- ग्रामीण विश्वविद्यालयों में लिखित व प्रयोगात्मक, दोनों ही परीक्षाएं स्नातक स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए।

वित्त -

- ग्रामीण विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित उत्तरदायित्व राज्यों का होना चाहिए।
- UGC द्वारा अनुदान का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(IV) भावनात्मक एकता समिति, 1961 –

राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं जैसे जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि को दूर करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने दो समितियों का गठन किया –

1. भावनात्मक एकता समिति
2. राष्ट्रीय एकता समिति

भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉ. संपूर्णानंद थे। इसका गठन 1961 में हुआ व राष्ट्रीय एकता समिति का गठन 1967 में व इसकी अध्यक्ष श्रीमती गांधी थी।

भावनात्मक एकता समिति की बैठक जून, 1968 में श्रीनगर में हुई, जहां पर राष्ट्रीय एकता विकास हेतु मुख्य-मुख्य उद्देश्यों की घोषणा की गई व राष्ट्रीय विकास की समस्या सुलझाने के लिए 3 उपसमितियों का गठन किया।

समिति के सुझाव –

(A) राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का उद्देश्य –

- सभी बालकों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जा सके।
- स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रमुख घटनाओं का ज्ञान कराया जाए।
- देश की विभिन्न जाति, संप्रदायों में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए शिक्षा पर विशेष बल।

(B) राष्ट्रीय एकता के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव –

- स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की जांच की जाए।
- इन पुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाली बातें निकाल दी जाए।
- सभी जातियों व धर्मों के लोग राष्ट्रीय व लोकप्रिय मेलों व त्योहारों में भाग ले।
- नाटकों व विवादों का आयोजन किया जाए।
- सांप्रदायिक एकता संबंधी विचारों के प्रसार के लिए रेडियो व समाचार-पत्रों का प्रयोग किया जाए।
- सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो न कि धर्म, प्रांत, सम्प्रदाय, जाति के आधार पर।

राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के लिए कार्यक्रम –

(i) प्राथमिक स्तर पर -

- बालकों को ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिह्न व राष्ट्रीय पक्षी व राष्ट्रीय पुष्प आदि का ज्ञान करवाए।
- स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस आदि राष्ट्रीय पर्व मनाए जाए।
- बाल दिवस, शिक्षक दिवस, गांधी जयंति जैसे दिवस मनाए जाए।
- महान व्यक्तियों के जीवन से परिचय, लोकगीत, कहानियों (विभिन्न क्षेत्रों की), सामाजिक जीवन का सरल परिचय, मानव भूगोल का थोड़ा ज्ञान दिया जाए।

(ii) माध्यमिक स्तर –

- बालकों में भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान कराए।
- विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक दशाएं व संस्कृति का ज्ञान कराया जाए।
- भारत के आर्थिक विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास, महापुरुषों संबंधी व्याख्यान, राष्ट्र भाषा के अधिक प्रयोग पर बल दिया जाए।

(iii) विश्वविद्यालय स्तर –

- छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए कि वे विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं, साहित्य व संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें।
- युवक उत्सवों का आयोजन किया जाए व विश्वविद्यालय के छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- समय-समय पर अध्ययन गोष्ठियों व विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाए व विश्वविद्यालयों के बालकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(IV) कोठारी आयोग, 1964 –

सरकार ने 14 जुलाई, 1964 में डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों व प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत व नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपना कार्य अक्टूबर, 1964 से शुरू किया। इसमें कुल 17 सदस्य शामिल थे।

इस आयोग ने 29 अगस्त, 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में शिक्षा के सभी परिवर्तनों और सुधारों के लिए इसका उल्लेख किया गया है।

आयोग के अनुसार शिक्षा तथा तथा अनुसंधान दोनों ही देश की समस्त आर्थिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास व प्रगति के लिए निर्णायक है। आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं -

- शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य का अनुभव व उत्पादन अनुभव आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- नैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया जाए।
- माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए।

- उन्नत अध्ययन केन्द्रों को अधिक सुदृढ बनाया जाए और बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी-सी संस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य रखे।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल व श्रेणी पर विशेष बल दिया जाए।
- शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि में शोध व इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हालांकि यह 20 वर्ष पुराना है, फिर भी अपनी खुशबू व ताजगी बनाए रखे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मुख्य रूप से इसकी सिफारिशों पर आधारित है, अतः यह शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है।

स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा

महत्वपूर्ण प्रश्न

Dr. Mukesh Pancholi

1. 1854-58 के दौरान किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी-

(A) कलकत्ता

(B) मद्रास

(C) पंजाब

(D) बॉम्बे

Dr. Mukesh Pancholi

2. भारत में शिक्षा का भविष्य निर्भर करता है -

(A) समाज

(B) सरकार

(C) परिवार

(D) अर्थव्यवस्था

Dr. Mukesh Pancholi

3. मुदालियर आयोग का संदर्भ था -

(A) प्राथमिक शिक्षा

(B) माध्यमिक शिक्षा

(C) उच्च शिक्षा

(D) सर्वांगीण शिक्षा

Dr. Mukesh Pancholi

4. जाकिर हुसैन समिति से जुड़ी आधुनिक शिक्षा की निम्न में से कौन-सी योजना है?

(A) हंटर शिक्षा आयोग

(B) हर्टोग योजना

(C) सार्जेंट शिक्षा आयोग

(D) वर्धा योजना

Dr. Mukesh Pancholi

5. के. एल. माली की अध्यक्षता में गठित आयोग संबंधित है -

- (A) ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा से
- (B) ग्रामीण क्षेत्रों की उच्च शिक्षा से
- (C) तकनीक व अनुसंधान की शिक्षा से
- (D) शिक्षक शिक्षण, प्रशिक्षण से

Dr. Mukesh Pathcholi

6. ग्रामीण शिक्षा आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों से संबंधित नहीं है -

(A) ग्रामीण उच्च शिक्षा व शिक्षकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय परिषद् का गठन।

(B) कृषि, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा के लिए महाविद्यालय व विश्व विद्यालय खोले जाएं।

(C) अध्ययन के साथ-साथ आय अर्जित करने के अवसर छात्रों को देना।

(D) ग्रामीण विश्वविद्यालयों में परीक्षा केवल लिखित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

7. भावनात्मक समिति के अध्यक्ष कौन थे -

(A) के. एल. माली

(B) जाकिर हुसैन

(C) डॉ. संपूर्णानंद

(D) श्रीमती गांधी

Dr. Mukesh Pancholi

8. डॉ. संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति की प्रथम बैठक कब व कहां हुई -

(A) जून, 1961, श्रीनगर

(B) जून, 1967, श्रीनगर

(C) जून, 1954, श्रीनगर

(D) जून, 1968, श्रीनगर

Dr. Mukesh Pancholi

9. विश्वविद्यालय स्तर पर भावनात्मक एकता जागृत करने से संबंधित सिफारिश नहीं है -

- (A) युवक उत्सवों का आयोजन
- (B) विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन
- (C) राष्ट्रभाषा के प्रयोग पर बल
- (D) इनमें से कोई नहीं

Dr. Mukesh Paricholi

10. किस समिति ने सिफारिश की, कि सरकारी पदों पर नियुक्ति जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत के आधार पर नहीं की जानी चाहिए -

- (A) संपूर्णानंद समिति
- (B) ग्रामीण शिक्षा समिति
- (C) मुदालियर आयोग
- (D) राधाकृष्णन आयोग

Dr. Mukesh Pancholi

11. कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया -

(A) 1964

(B) 1961

(C) 1948

(D) 1954

Dr. Mukesh Pancholi

12. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने कार्य प्रारंभ किया -

(A) 29 अगस्त, 1966

(B) अक्टूबर, 1964

(C) 14 जुलाई, 1964

(D) इनमें से कोई नहीं

Dr. Mukesh Pancholi

13. कोठारी आयोग संबंधित है -

- (A) राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा, सिद्धांत व नीतियों की रूपरेखा से संबंधित
- (B) ग्रामीण शिक्षा में सुधार
- (C) तकनीकी व उच्च शिक्षा में संभावनाओं का पता लगाना व सुझाव संबंधित
- (D) उपरोक्त सभी

Dr. Mukesh Pancholi

14. कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए -

(A) भावात्मक

(B) औपचारिक

(C) सामान्य शिक्षा से संबंधित

(D) व्यावसायिक

Dr. Mukesh Pancholi

15. कार्यानुभव, उत्पादन अनुभव को शिक्षा से जोड़ने का विचार किसने दिया था -

- (A) राधाकृष्णन आयोग
- (B) कोठारी आयोग
- (C) संपूर्णानंद आयोग
- (D) जाकिर हुसैन

Dr. Mukesh Pancholi